



मध्य प्रदेश में ठेके पर 11 हवाई पट्टी

मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश में हवाई सेवाओं का विस्तार करने के मकसद से 11 स्थान की हवाई पट्टी को निजी क्षेत्र को ठेके पर दे दिया गया है...

राइजिंग इन्दौर

■ रिपोर्टर

हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हवाई पट्टियों की संख्या बढ़ाई जा रही है। अभी आठ हवाई अड्डों के अलावा 23 हवाई पट्टियां हैं। यह उपयोग में रहें और बेहतर मेंटेनेंस होता रहे, इसके लिए 11 हवाई पट्टियां निजी संस्थाओं को उपयोग के लिए दी गई हैं।

सिवनी, ढाना (सागर), गुना, रतलाम, उज्जैन, बिरवा (बालाघाट), उमरिया, छिंदवाड़ा, मंदसौर, नीमच और शिवपुरी की हवाई पट्टी को उड़ान प्रशिक्षण, अन्य विमानन गतिविधियों के संचालन के लिए निजी संस्थाओं को सौंपा गया है। अधिकारियों के अनुसार शिवपुरी और उज्जैन की हवाई पट्टियों के विकास व विस्तार के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को जिम्मेदारी सौंपी गई है। हवाई पट्टियों को क्षेत्रीय हवाई अड्डों के रूप में विकसित किया जा रहा है।

नियमित हवाई सेवा के लिए जमीन अधिग्रहण शुरू

इससे नियमित हवाई सेवाएं शुरू की जा सकेंगी। इनके लिए जमीन अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है। केंद्र की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम (RCS) के तहत 2024-25 में दतिया हवाई पट्टी को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को दिया गया था। दतिया प्रदेश का 8वां एयरपोर्ट। यहां से छोटे विमानों का संचालन शुरू हो चुका है।

सरकार की इस पहल का बड़ा असर कहां?

सरकार की इस पहल का सबसे बड़ा असर प्रदेश के पर्यटन और औद्योगिक क्षेत्रों पर देखने को मिल सकता है। उज्जैन, छिंदवाड़ा, शिवपुरी और सिवनी जैसे शहर पहले से ही धार्मिक, प्राकृतिक और औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। लेकिन सीमित कनेक्टिविटी के कारण इनकी पूरी क्षमता का उपयोग ही नहीं हो पा रहा है। अब सेवाएं शुरू होने से इन क्षेत्रों में पर्यटकों की संख्या बढ़ने और निवेश आने की उम्मीद है।

टूरिज्म को बढ़ावा

खासतौर पर उज्जैन, जो महाकाल लोक के कारण देश-दुनिया भर के श्रद्धालुओं का प्रमुख केंद्र बन चुका है। वहां हवाई सुविधा बढ़ने से यात्रा और आसान हो जाएगी। इसी तरह शिवपुरी और बालाघाट जैसे क्षेत्र, जो नेशनल पार्क और प्राकृतिक पर्यटन के लिए जाने जाते हैं। वहां भी पर्यटकों की पहुंच बढ़ेगी।

स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा

इसके अलावा उड़ान प्रशिक्षण और एविएशन की गतिविधियों के शुरू होने से स्थानीय युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। पायलट ट्रेनिंग, ग्राउंड स्टाफ, मेंटेनेंस और अन्य तकनीकी क्षेत्रों में स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा।

समय पर जमीन अधिग्रहण से विकास तक का काम तो होगा बड़ा फायदा

हालांकि इस पूरी योजना में सफलता की कहानी इन हवाई पट्टियों का विकास समय पर पूरा होने पर निर्भर करेगी। एयरलाइंस कंपनियां इन रूट्स पर नियमित सेवाएं शुरू करें। जमीन अधिग्रहण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और संचालन से जुड़ी प्रक्रियाएं अगर तय समय सीमा में पूरी होती हैं, तो इसका पूरा फायदा प्रदेश को मिलेगा।

सरकार का पूरा फोकस फिलहाल छोटे शहरों को बड़े हवाई नेटवर्क से जोड़ने पर है। इससे आने वाले समय में मध्य प्रदेश के उभरते हवाई कनेक्टिविटी हब के रूप में भी सामने आ सकता है।



डबल डेकर ब्रिज के काम ने गति पकड़ी

राजिग इन्दौर
रिपोर्टर

इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा निर्मित किया जा रहे मध्य प्रदेश के पहले डबल डेकर ब्रिज के निर्माण कार्य में तेजी आ गई है। प्राधिकरण के द्वारा ठेकेदार फर्म पर दबाव बनाकर इस काम को गति के साथ करवाया जा रहा है।

उज्जैन रोड स्थित लवकुश चौराहे पर बन रहे प्रदेश के पहले डबल डेकर ब्रिज के मध्य हिस्से का काम अब रफ्तार पकड़ेगा। रविवार रात को ट्रैफिक रोककर 800 टन वजनी बो-स्ट्रिंग को स्थापित करने की कोशिश की गई। इसका थोड़ा सा हिस्सा खिसकाकर काम रोक दिया गया। इसे पुल पर स्थापित करने के लिए ट्रैफिक विभाग ने इंदौर-सावेर रोड का ट्रैफिक भी डायवर्ट किया था। अब फिर इसके लिए कवायद शुरू की जाएगी।

दोनों लेन पर 400-400 टन की बो-स्ट्रिंग गर्डर लगाई जाएगी। फिर उस पर ट्रैक बनेगा और ट्रैफिक गुजरेगा।



यह काम जमीन से 65 मीटर ऊंचाई पर होना है, इसलिए निर्माण एजेंसी ने विशालकाय क्रेनों की मदद ली। रविवार रात को इंदौर विकास प्राधिकरण के अधिकारी मौके पर पहुंचे। पहले मार्ग का ट्रैफिक रोका गया और दोनों तरफ क्रेनों ने मध्य हिस्से को आगे खिसकाना शुरू कर दिया। दो-तीन मीटर का हिस्सा खिसकाने के बाद काम रोक दिया गया।

तीन साल पहले शुरू हुआ था ब्रिज निर्माण- इंदौर में 175 करोड़ रुपये की लागत से यह ब्रिज तीन साल पहले बनना शुरू हुआ था।

इसकी लंबाई एक किलोमीटर से ज्यादा है। फरवरी में ही इसे पूरा हो जाना था, लेकिन काम की गति धीमी होने से देरी हो रही है। ब्रिज का 85 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है और 800 टन वजनी स्टील की बो-स्ट्रिंग चंडीगढ़ से बनकर आई है। अब उसे मध्य हिस्से में रखा जाएगा।

इस मार्ग के मध्य हिस्से में मेट्रो का ट्रैक भी है। इस कारण विशेष सावधानी बरती जा रही है, ताकि कोई परेशानी न हो। मध्य हिस्से के दोनों सिरे जुड़ने के बाद ब्रिज वर्षाकाल से पहले ट्रैफिक के लिए खोला जा सकता है। इसके निर्माण का सबसे

ज्यादा फायदा ढाई साल बाद उज्जैन में लगने वाले सिंहस्थ मेले के दौरान होगा। उज्जैन की ओर सबसे ज्यादा ट्रैफिक इंदौर से होकर गुजरेगा।

धनुषाकार होती है बो-स्ट्रिंग गर्डर

दरअसल, बो-स्ट्रिंग ब्रिज एक विशेष प्रकार का धनुषाकार पुल होता है। इसका ऊपरी हिस्सा एक धनुष की तरह मुड़ा हुआ होता है और नीचे का हिस्सा एक सीधी रस्सी या स्ट्रिंग की तरह होता है। इसके जरिए पुल के ऊपर से गुजरने वाले वाहनों का भार इसके झुके हुए मेहराबों द्वारा संभाला जाता है। यह 50-150 मीटर की दूरी के लिए बहुत उपयुक्त है और मुख्य रूप से वहां इस्तेमाल होता है। जहां जमीन कमजोर हो या जहां खंभे लगाना मुश्किल हो। ये पुल देखने में आकर्षक, भूकंप-रोधी, और टिकाऊ होते हैं। इनका निर्माण दूसरी जगह करवा कर निश्चित स्थान पर इन्हें स्थापित जा सकता है। भारत में इनका उपयोग रेलवे ओवर ब्रिज और मुंबई व चेन्नई जैसे तटीय शहरों में सड़कों पर किया जा रहा है।

खजराना गणेश मंदिर के पुजारी ने एक करोड़ का दहेज मांगा

राजिग इन्दौर
रिपोर्टर

प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर से जुड़े परिवार की बहू इंदिरा भट्ट ने अपने पति पुनीत भट्ट और ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस कमिश्नर कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता का आरोप है कि उससे दहेज मांगा गया।

इंदिरा भट्ट ने अपने पति पुनीत भट्ट और ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस आयुक्त कार्यालय में गृहण लगाई है। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि उसे दहेज के लिए न केवल शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, बल्कि जबरन घर से भी निकाल दिया गया है। इंदिरा के मुताबिक उनकी शादी 17 मई 2025 को संपन्न हुई थी। उन्होंने बताया कि यह उन दोनों की दूसरी शादी थी और पति ने संतान प्राप्ति की इच्छा के चलते उनसे विवाह किया था। शुरुआती दो महीनों तक स्थिति सामान्य रही लेकिन जुलाई 2025 के बाद ससुराल वालों का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। आरोप है कि पति, सास, ननंद, नंदोई और देवरों ने मिलकर उन पर मायके से 1 करोड़ रुपए नकद और एक फॉर्च्यूनर कार लाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया था।

मुख्य से तड़पाने का आरोप

पीड़िता ने अपनी शिकायत में अत्यंत मार्मिक आरोप लगाए हैं। इंदिरा का कहना है कि ससुराल में उन्हें कई बार भोजन तक नहीं दिया जाता था और उन्हें घर के भीतर ही बंद करके रखा जाता था। इतना ही नहीं, उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने से रोकने के लिए नौकरी करने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। जब भी उन्होंने इन बातों का विरोध किया, तो उनके पति उन्हें अलग कमरे में ले जाकर धमकाते थे। इंदिरा का दावा है कि उनके ससुराल पक्ष ने उनके कीमती जेवर और लगभग 5 लाख रुपए नकद भी अपने कब्जे में ले लिए हैं और मांगने पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है।

दत्तक पुत्र की पत्नी के गर्भवती होने पर बदला व्यवहार

शिकायत पत्र में इंदिरा ने एक विशेष घटनाक्रम का उल्लेख किया है। उन्होंने बताया कि उनके पति पुनीत भट्ट की अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने बड़े पिता के पुत्र उदित को गोद लिया था। शादी के शुरुआती समय में सब ठीक था, लेकिन जैसे ही जुलाई 2025 में यह सूचना मिली कि दत्तक पुत्र उदित की पत्नी गर्भवती है, वैसे ही ससुराल वालों का रवैया इंदिरा के प्रति क्रूर हो गया। आरोप है कि इसके बाद से ही 1 करोड़ रुपए और महंगी कार की मांग तेज कर दी गई और स्पष्ट कहा गया कि यह मांग पूरी होने पर ही उन्हें शांति से रहने दिया जाएगा।

झूठे मुकदमों में फंसाने की साजिश

इंदिरा भट्ट ने आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ सुनियोजित तरीके से साजिश रची गई। उनके पति के दत्तक पुत्र उदित ने अपनी पत्नी के माध्यम से इंदिरा पर गलत आरोप लगाकर एक मामला दर्ज करवाया, जिसमें खजराना पुलिस ने कोर्ट में चालान भी पेश कर दिया है। पीड़िता का कहना है कि यह सब उन्हें परेशान करने और दबाव में लाने के लिए किया गया है। सितंबर 2025 में मारपीट कर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया था, जिसके बाद से वह अपने मायके में रहने को विवश हैं। ससुराल पक्ष अब उन्हें अपने प्रभाव का डर दिखाकर पुलिस कार्रवाई न होने देने की धमकी दे रहा है। फिलहाल पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आवेदन प्राप्त हो गया है और जांच के बाद उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

नारी तू नारायणी, किया महिलाओं का सम्मान

राजिग इन्दौर
रिपोर्टर

मां अहिल्या सेवा संस्था और विश्व हिंदी अकादमी के द्वारा महिला दिवस के अवसर पर नारी तू नारायणी कार्यक्रम का आयोजन रिविंद नाट्य ग्रह में किया गया। संस्था डायरेक्टर डॉ. आरती मेहरा ने बताया कि प्रोग्राम में नारी के हर रूप को सम्मानित कर गौरवांचित किया गया। इस अवसर पर मातृशक्ति को दुर्गा की अष्ट शक्तियों के रूप में मानते हुए उनके विभिन्न कौशल, प्रतिभा और समाज के अलग-अलग क्षेत्रों में उनकी पारंगतता को सराहा गया। विश्व



हिंदी अकादमी के अध्यक्ष केशव राय ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं की शक्ति, क्षमता और समाज में उनके महत्वपूर्ण योगदान को सम्मान देना था। कार्यक्रम में मेजर डॉ. अनामिका जैन होलकर

कॉलेज प्रिंसिपल, एडिशनल एसपी विक्रम अर्वाडी गीता चौहान, भास्कर की पत्रकार नीता सिसोदिया और आरएसएस की मातृशक्ति को आगे बढ़ाने वाली आरती जायसवाल, प्रसिद्ध सिंगर डॉ. अनामिका जैन होलकर

एनजीओ डायरेक्टर डॉ. जानवी चंदवानी, वरिष्ठ चित्रकार शुभा वैध और विभिन्न क्षेत्रों में प्रसिद्ध पारंगत महिलाओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चिंतन बाकीवाला थे। जिन्होंने कहा कि नारी कभी बेटी बनकर घर में खुशियां लाती है। कभी मन बनाकर दुनिया को संस्कार सिखाती है तो वहीं दुर्गा बनकर अन्याय से लड़ जाती है। कार्यक्रम का संयोजन संस्था उपाध्यक्ष रश्मि बाकीवाला और संजय मेहरा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में रचना गुप्ता, मीना काले, अनामिका बाकलीवाल, सिम्मी सलूजा, गायत्री गुप्ता, सुमन जायसवाल, रेखा साधवानी भी उपस्थित थे।

इंदौर के अग्निकांड पर रिसर्च करेगा मैनिट पहली बार प्रौद्योगिकी संस्थान ने इंदौर की घटना को चुनौती के रूप में लिया

राजिग इन्दौर
रिपोर्टर

बंगाली चौराहे के पास मकान में आग लगने और उस आग में आठ लोगों के जिंदा जलकर मर जाने की घटना पर मैनिट के द्वारा रिसर्च की जाएगी। यह पहला मौका है जब इंदौर की किसी घटना पर प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा रिसर्च शुरू की जा रही है।

पिछले दिनों बंगाली चौराहा के समीप एक मकान में रात के समय पर आग लगने की घटना घटित हुई थी। इस घटना में आठ लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई थी। इस घटना को एक चुनौती के रूप में मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मैनिट ने लिया है। इस संस्थान के द्वारा अब इस घटना पर रिसर्च की जाएगी। इस रिसर्च का उद्देश्य यह है कि इस तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल में दोबारा ऐसी घटना होने से किस तरह से रोका जा सकता है। इंदौर की इस घटना से

इलेक्ट्रिक वाहनों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होना शुरू हो गए हैं।

इंदौर की घटना का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट बताया जाता है। सरकार के द्वारा अब तक यह दावा किया जा रहा था कि इलेक्ट्रिक वाहन में जब बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो जाती है तो उसके बाद में ऑटोमेटिक पावर कट हो जाता है। वाहन निर्माता कंपनियों के द्वारा भी इसी तरह का दावा किया जा रहा था। अब ऐसी स्थिति में सवाल यह है कि जब इलेक्ट्रिक व्हीकल में ऑटो पावर कट का सिस्टम होता है तो फिर वहां में आग कैसे लग सकती है।

इस प्रौद्योगिकी संस्थान के इलेक्ट्रिकल विभाग के प्रोफेसर शैलेंद्र जैन का कहना है कि इन वाहनों का उपयोग करने वालों को दिए गए मैनुअल को अच्छे से पढ़ना चाहिए। इस मैनुअल के हिसाब से ही इन वाहनों का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा वाहनों के उपयोग के

समय रखरखाव को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। कंपनी के द्वारा दिए गए समय पर वाहनों की सर्विसिंग करवाई जाना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो इस तरह की घटना कभी भी नहीं होगी।



इस प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा इंदौर की घटना को इलेक्ट्रिक व्हीकल के उपयोग का एक सबक के रूप में हाथ में लिया गया है। इस संस्थान के इलेक्ट्रिकल विभाग में प्रवेश लेकर अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों को भी

उक्त घटना का अध्ययन कराया जाएगा ताकि वह अपनी सर्विस के दौरान वाहनों के फीचर के संबंध में सुरक्षा दे सके। इस रिसर्च के लिए इस प्रौद्योगिकी संस्थान के भोपाल के प्रोफेसर और विद्यार्थी इंदौर आकर काम करेंगे। घटनास्थल का मुआयना भी करेंगे और वहां का बारीकी से परीक्षण भी किया जाएगा। ध्यान रहे कि बढ़ती महंगाई के कारण इलेक्ट्रिकल व्हीकल का उपयोग बढ़ गया है। ऐसे में इस तरह की घटना देश में सभी लोगों को चेतावनी देता है। खास तौर पर वे लोग जो की इलेक्ट्रिकल व्हीकल के माध्यम से अपना काम करते हैं उनके लिए एक अलार्म बज गया है। इस संस्थान के द्वारा अपनी रिसर्च के माध्यम से यह देखा जाएगा कि इन वाहनों को की डिजाइन में कौन सा फीचर और जोड़ा जाना चाहिए जिससे कि इस तरह की घटनाओं को होने से रोका जा सके।

राजिग इन्दौर

रिपोर्टर

इंदौर नगर निगम के द्वारा भुरी टेकरी पर पूर्व से बनाए गए 976 फ्लैट का रिनोवेशन कराया जाएगा। यह काम निजी क्षेत्र के बिल्डर को पार्टनर बनाकर नगर निगम करवाएगा।

नगर निगम का बजट सम्मेलन 28 मार्च को होगा। निगम मुख्यालय स्थित श्री अटल बिहारी वाजपेयी परिषद सभागृह यानी अटल सदन में सुबह 11 बजे महापौर पुष्पमित्र भार्गव अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश करेंगे। बजट पर बहस 30 मार्च को होगी। बजट के साथ 54 से ज्यादा प्रस्तावों को भी मंजूरी दी जाएगी। इसमें एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत भुरी टेकरी पर बनी बहुमंजिला आवासीय इकाइयों के 976 फ्लैट का पुनर्विकास (रिनोवेशन) करना है। यह काम पीपीपी मॉडल पर होगा।

प्रमुखता से उठाया गया था मुद्दा

दरअसल, भुरी टेकरी पर बने फ्लैट के लंबे समय से खराब हालत में होने, रहवासियों के लिए जान का खतरा बनने, बरसात के दिनों में घरों के अंदर पानी टपकने और इमारत की हालत जर्जर होने का मुद्दा पिछले काफी समय से लगातार उठ रहा है। इसके बाद निगम के अफसर हरकत में आए और भुरी टेकरी के फ्लैट का निरीक्षण कर स्थिति का आंकलन किया। साथ ही खसरा क्रमांक 1/1/1 के 8.07 हेक्टेयर आवंटित भूमि पर बनाई गई बहुमंजिला इमारतों में 976 फ्लैट का पुनर्विकास पीपीपी मॉडल यानी पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप पर करने का प्रस्ताव तैयार कर एमआईसी में रखा गया। एमआईसी से

प्राइवेट बिल्डर को बनाएंगे पार्टनर और करवाएंगे काम



संकल्प पारित होने पर अब प्रस्ताव को 28 मार्च को होने वाली निगम परिषद की बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा।

इस प्रस्ताव के साथ वित्तीय वर्ष 26-27 का बजट भी स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। इस बार के बजट में निगम ने न तो नया टैक्स लगाया और न ही पुराने में कोई बढ़ोतरी की है। इससे आमजन को राहत है। तकरीबन 8500 करोड़ रुपए के बजट में शहर के विकास, कर्मचारियों के हितों और जनता को राहत देने पर फोकस किया गया है। सभापति मुन्नालाल यादव की अध्यक्षता में महापौर भार्गव अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश करेंगे।

इन प्रस्तावों को रखेंगे परिषद में

■ नेहरू पार्क एवं महानाका स्वीमिंग पूल के किराए व सदस्यता शुल्क बढ़ाना।

■ शहरी सीमा क्षेत्र के फ्लाईओवर और पुलपुलियाओं के ऊपरी भाग पर हरित क्षेत्र निर्मित कर सौंदर्यीकरण करना।

■ जलउपभोक्ता प्रभार की दरों का युक्तियुक्तकरण और बिलिंग प्रक्रिया का मानकीकरण करना।

■ नगरीय क्षेत्र में वृक्ष कटाई, छंटाई एवं ट्रांसप्लांट (प्रत्यारोपण) करने के लिए निर्धारित शुल्क में वृद्धि करना।

■ श्री गणेश विसर्जन चल समारोह में शामिल अखाड़ों को अनुदान राशि में वृद्धि करना।

■ नगर निगम कार्यार्थ विभिन्न प्रकार के नवीन वाहन खरीदना।

■ आगरा-बॉम्बे (एबी) रोड का नाम अटल बिहारी मार्ग करना।

■ रणजीत हनुमान मंदिर के आगे आदित्य हॉस्पिटल के पास के चौक का नाम अभिग्रह चौक और गुमाश्ता नगर दिगंबर जैन मंदिर की

ओर जाने वाले मार्ग का नाम राजेश मुनि मार्ग करना।

■ अमृत-2.0 योजना अन्तर्गत जलप्रदाय एवं सीवरेज संबंधी कार्यों के क्रियान्वयन के लिए 1530 करोड़ का लोन लेना।

■ खाली दुकानों को यथास्थिति में प्रवेश अधिकार शुल्क एवं मासिक किराए की दर पर 30 वर्षों के लिए आबंटन करना।

■ स्ट्रीट डॉग की देखरेख व सुचारु व्यवस्था करने की कार्य योजना का प्रारूप बनाना।

■ निगम द्वारा संपादित किए जाने वाले विभिन्न शासकीय विभागों से संबंधित कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए सुपरविजन चार्ज निर्धारित करना।

■ नर्मदा चौथे चरण के तहत शहर में 24 घंटे 7 दिन पानी देने के साथ नई टकी का निर्माण करने के साथ सप्लाय लाइन डालने के ठेके को स्वीकृति देना।

■ नगरीय सीमा क्षेत्र में आने वाले समस्त ठोस अपशिष्ट उत्पादकों (30 किलो व अधिक) के कचरे के संग्रहण एवं निपटान के लिए भवन निर्माण अनुमति में नियमावली शामिल करना।

■ सीएंडडी वेस्ट के संग्रहण, ट्रांसपोर्टेशन एवं प्रोसेसिंग कर निपटान के लिए 200 टीपीडी क्षमता का प्लांट लगाना।

■ सरवटे बेसमेंट पार्किंग, महाराजा कॉम्प्लेक्स पार्किंग को पीपीपी मोड पर 5 साल के लिए ठेके पर देना। 6 पार्किंग के लिए पीपीपी मोड पर टेंडर बुलाना।

■ शहर के विभिन्न स्थानों पर स्थापित निगम स्वामित्व की 44 ग्रेट्री एवं 3 फुट ओवर ब्रिज (पैदल पुल) पर 05 वर्षों के लिए विज्ञापन के अधिकार देना।

■ 6 युनिपोल और एलडी स्क्रीन को ठेके पर देने के लिए बुलाए टेंडर को मंजूरी देना।

राजिग इन्दौर

रिपोर्टर

समीक्षा बैठक के माध्यम से कांग्रेस ने शुरू की निगम चुनाव की तैयारी

इंदौर। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महासचिव हरीश चौधरी ने कहा है कि ब्लॉक स्तर की कांग्रेस ही असली कांग्रेस है। कांग्रेस में अब बड़े नेताओं की परिक्रमा करने से पद नहीं मिलेगा बल्कि मैदान में मेहनत करने से ही पद मिलेगा। अगले साल इंदौर नगर निगम के चुनाव होना है। इस चुनाव के लिए ताकत लगाकर अभी से तैयारी शुरू की जाए।

चौधरी ने यह निर्देश आज संगठन सृजन अभियान के तहत नियुक्त किए गए कांग्रेस के पदाधिकारी को संबोधित करते हुए दिए। कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन पर आज शहर कांग्रेस की नव घोषित की गई कार्यकारिणी के साथ ही सभी ब्लॉक अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, मंडलम सेक्टर प्रभारी, बूथ अध्यक्ष, विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारी, मोर्चा संगठन के अध्यक्ष गण, एनएसयूआई महिला कांग्रेस यूथ कांग्रेस सेवा दल के सभी पदाधिकारी की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में दिए गए अपने संबोधन में चौधरी ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की। उन्होंने स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करते हुए कहा कि इंदौर नगर निगम के चुनाव अगले वर्ष 2027 में होना है। कांग्रेस से कार्यकर्ताओं को अब इस चुनाव की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। आपको शहर कांग्रेस के माध्यम से आपके वार्ड की मतदाता सूची मिल जाएगी। इस मतदाता सूची को चेक की जाए। इसमें



ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ही असली कांग्रेस, अब परिक्रमा से नहीं मेहनत से पद मिलेगा - चौधरी एक होकर मैदान संभालो और निगम का चुनाव जीत कर आओ - पटवारी

जिस भी मतदाता का नाम छूट रहा है तो उसका नाम जोड़ने की कार्रवाई की जाए। जो मतदाता क्षेत्र छोड़कर चले गए हैं या जिनकी मृत्यु हो गई है उनके नाम यदि सूची में मौजूद हो तो उन्हें हटाने के लिए भी कार्रवाई की जाए।

चौधरी ने कहा कि अभी से आप मतदाता सूची चेक करने के साथ अपना काम करना शुरू करेंगे तो आप चुनाव बेहतर तरीके से लड़ सकेंगे। कांग्रेस की ब्लॉक कमेटी और वार्ड कमेटी इस चुनाव का नेतृत्व करेंगी। उन्हें ही चुनाव

के लिए व्यापक पैमाने पर तैयारी करना है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि तैयारी में कभी भी किसी भी स्तर पर कोई कमी नहीं रह जाए।

इस बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि अब हमें अपनी पूरी ताकत अगले साल होने वाले नगर निगम के चुनाव में लगा देना है। कांग्रेस में हर कार्यकर्ता का महत्व है। कोई जरूरी नहीं है कि आप बड़े-बड़े कार्यक्रम का आयोजन करें और बड़ा समियाना लगे। आवश्यकता



तो इस बात की है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के सुख और दुख में सहभागी बनें। इंदौर के भागीरथ पुपा हादसे की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा पूरे प्रदेश में होने वाली घटनाओं के लिए अधिकारियों को जिम्मेदार बताया जा रहा है और उन पर कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश सरकार के जो मंत्री नेता महापौर जिम्मेदार हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। भागीरथपुरा की घटना के लिए प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री और क्षेत्र के विधायक कैलाश विजयवर्गीय पूरी

तरह से जिम्मेदार है। इसके बावजूद उन्हें मंत्री पद से नहीं हटाया गया है। हमें प्रदेश सरकार की असफलताओं की जानकारी जनता के बीच पहुंचाना होगा। इस बैठक को इंदौर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष चिंटू चौकसे, कांग्रेस के नेता अमन बजाज ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन देवेन्द्र सिंह यादव और संजय बाकलीवाल ने किया। इस कार्यक्रम में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 के प्रभारी शैलेश गर्ग को इस विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची भेंट की गई।

संपादकीय...



शहर की घटनाओं से हमें सबक लेना होगा

शहर में एक के बाद एक जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं उसे देखते हुए शहर की जनता को जिला प्रशासन को और नगर निगम को सबक सिखाने की आवश्यकता है। हाल ही में बंगाली चौराहे के समीप एक कॉलोनी में रात के समय में एक मकान में आग लगने से आठ लोगों की मौत हो गई। इस घटना में फायर ब्रिगेड को सूचना दिए जाने के बाद डेढ़ घंटे विलंब से घटनास्थल पर पहुंचने की बात भी सामने आई है। इस तरह की घटनाएं हमें आने



■ गौरव गुप्ता

वाले कल के लिए चेतावनी देती हुई नजर आ रही है। इस चेतावनी को समझते हुए हमें भविष्य की तैयारी को आकार देना चाहिए। इंदौर नगर निगम को भी चाहिए कि जिस तरह की घटनाएं शहर में हो रही हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए आगे के लिए तैयारी करें और इस तैयारी की झलक नगर निगम के आने वाले बजट में नजर आ जाना चाहिए। यदि बजट में इन घटनाओं को रोकने के उपाय नजर नहीं आते हैं तो इससे स्पष्ट है कि इन घटनाओं से नगर निगम सबक नहीं सीख रहा है।

हीटवेव से अपच तक को दूर करने में कारगर, और गर्मी में सेहत के लिए वरदान से कम नहीं नीम के फूल और पत्तियां

तपती धूप, लू और आसमान से बरसती आग, इन सबके बीच सेहतमंद बने रहना भी किसी चुनौती से कम नहीं होता

डॉक्टर आरती मेहरा ने बताया कि गर्मी के मौसम ने दस्तक दे दी है। तपती धूप, लू और आसमान से बरसती आग से इस मौसम में रोजमर्रा की जिंदगी में स्वस्थ रहना मुश्किल हो जाता है। आयुर्वेद इस मौसम की परेशानियों से बचने के लिए नीम के फूलों और पत्तियों के सेवन करने की सलाह देता है। ये छोटे, सुगंधित फूल शरीर को ठंडक पहुंचाते हैं, खून साफ करते हैं, अपच-कब्ज जैसी पेट की समस्याओं को दूर करते हैं और त्वचा को चमकदार बनाते हैं।

इनमें ढेर सारे औषधीय गुण छिपे हैं नीम की पत्तियां कड़वी होने के कारण सब जानते हैं, लेकिन इसके छोटे-छोटे फूल भी कम फायदेमंद नहीं हैं। गर्मी के दिनों में दादी-नानी अक्सर नीम के फूलों से बनी शरबत या भुजिया खिलाती थीं। ये फूल न सिर्फ सौंधी खुशबू वाले और सुंदर होते हैं, बल्कि इनमें ढेर सारे औषधीय गुण छिपे हैं जो गर्मी की मार से बचाते हैं।

आयुर्वेद में नीम के फूलों और पत्तियों को बहुत कारगर माना जाता है। क्लोरोफॉर्म, एथिल एसीटेट, इथेनॉल और मेथनॉल जैसे सॉल्वेंट्स से निकाले गए अर्कों की जांच में पाया गया कि इथेनॉलिक अर्क डायबिटीज और कैंसर कोशिकाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा प्रभावी है। यह अन्य पौधों के भागों की तुलना में कम हानिकारक और ज्यादा लाभकारी साबित हुआ। आयुर्वेद में नीम के फूलों और पत्तियों को बहुत कारगर माना जाता है। इनमें एंटी-फंगल, एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-सेप्टिक गुण होते हैं।



डॉ. आरती मेहरा
आहार एवं पोषण विशेषज्ञ
7999788456

नीम के फूल और पत्ती के प्रमुख स्वास्थ्य लाभ इस प्रकार हैं-

त्वचा के लिए वरदान
नीम के पत्तों में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, जो मुंहासे (acne), रैशेज, घाव और अन्य त्वचा संक्रमणों को दूर करने में मदद करते हैं।
इम्यूनिटी और पाचन- खाली पेट नीम के पत्ते खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) बढ़ती है और पेट के कीड़े खत्म होते हैं।
रक्त शर्करा (Diabetes) नियंत्रण- नीम में हाइपोग्लाइसेमिक प्रभाव होता है, जो ब्लड शुगर को कम करने और नियंत्रित करने में मदद करता है।
बालों के लिए- नीम का पानी बालों की रूसी



(dandruff) को दूर करता है और स्कैल्प को स्वस्थ बनाकर बालों को मजबूत बनाता है।

मसूड़ों और ओरल हेल्थ- नीम की पत्तियां या टहनी मसूड़ों की सूजन और कैविटी को कम करने में मदद करती हैं।

लीवर और टॉक्सिन्स- यह शरीर से विषैले पदार्थों (toxins) को बाहर निकालकर लीवर के स्वास्थ्य में सुधार करता है।

सावधानी- नीम का सेवन बहुत अधिक मात्रा में न करें, क्योंकि इससे शरीर में वात बढ़ सकता है। इसे कम समय के लिए (जैसे वसंत ऋतु में) ही लेना बेहतर होता है।

नीम की पत्ती खाने के नुकसान

1. नीम की पत्ती खाने से ब्लड शुगर बहुत कम हो सकता है।
नीम की पत्तियां ब्लड शुगर को कम करने में मदद करती हैं, लेकिन अगर इन्हें ज्यादा मात्रा में या लंबे समय तक खाया जाए, तो शुगर लेवल जरूरत से ज्यादा गिर सकता है। इससे चक्कर आना, कमजोरी, पसीना आना और बेहोशी जैसी समस्याएं हो सकती हैं, खासकर डायबिटीज की दवा लेने वालों में।
2. नीम की पत्ती खाने से पेट से जुड़ी समस्याएं
नीम की पत्ती का स्वाद बहुत कड़वा होता है। ज्यादा मात्रा में सेवन करने पर यह पेट में जलन, मरोड़, मतली या दस्त जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है।
3. चेहरे पर नीम लगाने से एलर्जी या जलन
हर स्किन टाइप के लिए नीम सूट करे, यह जरूरी नहीं है।
4. गर्भावस्था और स्तनपान में नीम की पत्ती या

नीम से बने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल सुरक्षित नहीं माना जाता।

5. बच्चों में नीम की पत्ती का सेवन खतरनाक हो सकता है। बच्चों का पाचन तंत्र संवेदनशील होता है। इसलिए बच्चों को नीम खिलाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूरी है।
6. नीम तेल पीने से- लिवर और किडनी को नुकसान, उल्टी और बेहोशी। नीम तेल केवल बाहरी इस्तेमाल के लिए ही सुरक्षित माना जाता है।
7. दवाओं के साथ नीम की पत्ती लेने के नुकसान
अगर आप पहले से डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ब्लड पतला करने की दवाएं, ले रहे हैं, तो नीम की पत्तियां या नीम सप्लीमेंट्स उनके असर को जरूरत से ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इससे दवाओं के साथ खतरनाक रिएक्शन हो सकता है।

नीम का सही इस्तेमाल कैसे करें

(नीम की पत्ती, पाउडर, काढ़ा, टिंचर और तेल) नीम से सही फायदा तभी मिलता है जब इसका सही रूप, सही मात्रा और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि नीम औषधीय पौधा है, इसलिए इसे रोजमर्रा की चीजों की तरह नहीं, बल्कि नियंत्रित रूप में अपनाना चाहिए।

1. नीम की पत्ती का सेवन विधि

- सुबह खाली पेट 3 -6 ताजी नीम की पत्तियां चबाई जा सकती हैं।
- कड़वाहट ज्यादा लगे तो पत्तियों को पानी में उबालकर छान लें और उसका हल्का काढ़ा पिएं।
- लंबे समय तक रोज सेवन करने से पहले ब्रेक लेना जरूरी होता है।
- डायबिटीज, लो BP या पेट की समस्या वाले लोग रोज नीम की पत्तियां खाने से पहले डॉक्टर से सलाह लें।

2. नीम पाउडर का उपयोग

- दिन में ¼ से ½ चम्मच नीम पाउडर पर्याप्त होता है।
- इसे गुनगुने पानी, शहद या ग्रीन टी के साथ लिया जा सकता है।
- त्वचा और खून की सफाई के लिए सीमित समय तक उपयोग बेहतर रहता है।

3. नीम काढ़ (काढ़ा)

- सूखी नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर काढ़ा बनाया जाता है।
- स्किन प्रॉब्लम और डिटॉक्स के लिए हफ्ते में 2-3 बार लिया जा सकता है।
- ज्यादा तेज या ज्यादा मात्रा में पीना नुकसानदायक हो सकता है।

4. नीम टिंचर

- आमतौर पर 15-20 बूंद, दिन में 1-2 बार लेने की सलाह दी जाती है।
- सही मात्रा व्यक्ति की उम्र, समस्या और शरीर की स्थिति पर निर्भर करती है।
- इसलिए टिंचर का उपयोग आयुर्वेद विशेषज्ञ की सलाह से करना बेहतर होता है।

5. नीम कैप्सूल या टैबलेट

- खाने के बाद दिन में 1 कैप्सूल, दिन में 1-2 बार।
- शुगर कंट्रोल, स्किन प्रॉब्लम और इम्यूनिटी सपोर्ट के लिए उपयोग किया जाता है।
- लंबे समय तक सेवन करने से पहले ब्रेक और मॉनिटरिंग जरूरी है।

6. नीम तेल का सही उपयोग

- नीम तेल को कभी भी पीना नहीं चाहिए।
- इसे हमेशा नारियल, तिल या ऑलिव ऑयल में मिलाकर ही त्वचा या बालों पर लगाएं।
- डैंड्रफ, जू, घाव और फंगल इंफेक्शन में बाहरी रूप से उपयोग फायदेमंद होता है।

नीम के औषधीय गुण

- नीम में ऐसे प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं जो इसे एक बहुउपयोगी औषधीय पौधा बनाते हैं। अब तक किए गए अध्ययनों में नीम के अलग-अलग हिस्सों से 140 से अधिक बायोएक्टिव (जैव-सक्रिय) तत्वों की पहचान की जा चुकी है। यही तत्व नीम को आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा दोनों में खास स्थान दिलाते हैं।
नीम के पत्ते, फूल, बीज, फल, जड़ें, छाल में औषधीय गुण पाए जाते हैं, इन सभी हिस्सों में मौजूद प्राकृतिक यौगिक शरीर को डिटॉक्स करने, संक्रमण से बचाने और अंदरूनी सूजन को कम करने में मदद करते हैं।

महिलाओं के कानूनी अधिकार

भारत में महिलाओं को समाज में समान स्थान दिलाने के लिए संविधान तथा विभिन्न कानूनों के माध्यम से अनेक अधिकार प्रदान किए गए हैं। समय के साथ-साथ न्यायपालिका और सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और समानता सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कानून बनाए हैं। बेटी और महिलाओं के कानूनी अधिकारों का उद्देश्य उन्हें शोषण, हिंसा और भेदभाव से बचाना तथा उन्हें समान अवसर प्रदान करना है।



1. संविधान द्वारा दिए गए अधिकार
भारत का संविधान महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देता है।

संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार सभी नागरिक कानून की दृष्टि में समान हैं। इसका अर्थ है कि महिला और पुरुष दोनों को समान अधिकार प्राप्त हैं।

अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। साथ ही सरकार महिलाओं और बच्चों के हित में विशेष प्रावधान बना सकती है।

अनुच्छेद 16 के अनुसार सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं को समान अवसर का अधिकार है।

2. बेटी का संपत्ति में अधिकार

पहले हिंदू परिवारों में बेटियों को संपत्ति में बराबर का अधिकार नहीं मिलता था, लेकिन हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 के बाद बेटियों को पुत्रों के समान पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया गया है।

अब बेटी भी अपने पिता की संपत्ति में उतनी ही हिस्सेदार है जितना बेटा। चाहे बेटी शादीशुदा हो या अविवाहित, उसका अधिकार बना रहता है।

3. घरेलू हिंसा से सुरक्षा का अधिकार

महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 बनाया गया है। इस कानून के अंतर्गत किसी भी महिला को यदि पति, ससुराल या परिवार के अन्य सदस्य द्वारा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या भावनात्मक प्रताड़ना दी जाती है तो वह न्यायालय में शिकायत कर सकती है। इस कानून के तहत महिला को निम्नलिखित अधिकार मिलते हैं -

जाती है तो वह न्यायालय में शिकायत कर सकती है। इस कानून के तहत महिला को निम्नलिखित अधिकार मिलते हैं -

- » सुरक्षा आदेश
- » निवास का अधिकार
- » भरण-पोषण का अधिकार
- » मुआवजा पाने का अधिकार

4. कार्यस्थल पर सुरक्षा का अधिकार

महिलाओं को कार्यस्थल पर सम्मानजनक वातावरण प्रदान करने के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और प्रतिरोध) अधिनियम 2013 लागू किया गया है।

इस कानून के अनुसार किसी भी संस्था या कार्यालय में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न करना अपराध है। प्रत्येक संस्था में शिकायत समिति बनाना अनिवार्य है, जहां महिला अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है।

5. दहेज से सुरक्षा का अधिकार

भारतीय समाज में दहेज प्रथा एक गंभीर समस्या रही है। इसे रोकने के लिए दहेज निषेध अधिनियम 1961 लागू किया गया है। इस कानून के तहत दहेज लेना और देना दोनों अपराध हैं। यदि किसी महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है तो वह पुलिस में शिकायत कर सकती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 498A भी इस प्रकार के मामलों में लागू

होती है।

6. भरण-पोषण का अधिकार

यदि पति अपनी पत्नी का पालन-पोषण नहीं करता या उसे छोड़ देता है तो महिला को भरण-पोषण पाने का अधिकार है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत पत्नी न्यायालय में आवेदन कर सकती है और न्यायालय पति को भरण-पोषण देने का आदेश दे सकता है।

यह अधिकार केवल पत्नी को ही नहीं बल्कि बच्चों और माता-पिता को भी प्राप्त है।

7. मातृत्व का अधिकार

कामकाजी महिलाओं को मातृत्व के समय विशेष सुविधा देने के लिए मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 बनाया गया है। इस कानून के अनुसार महिला कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश और आर्थिक लाभ दिए जाते हैं।

संशोधित प्रावधानों के अनुसार कई संस्थानों में महिलाओं को 26 सप्ताह तक का मातृत्व अवकाश दिया जाता है।

8. बेटी की शिक्षा का अधिकार

सरकार ने बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। इसके साथ ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है।

9. बलात्कार और यौन अपराधों से सुरक्षा

महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए भारतीय दंड संहिता में कई कठोर प्रावधान किए गए हैं। बलात्कार, छेड़छाड़ और अन्य यौन अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों को रोकने के लिए POCSO Act लागू किया गया है, जो बच्चियों की विशेष सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

10. न्यायालय की महत्वपूर्ण भूमिका

भारत की न्यायपालिका ने भी महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समय-समय पर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे कई निर्णय दिए हैं जिनसे महिलाओं की गरिमा और समानता को बल मिला है।

न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव संविधान के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है।

निष्कर्ष

आज के समय में महिलाओं और बेटियों के लिए कई कानूनी अधिकार और सुरक्षा के प्रावधान मौजूद हैं, लेकिन इन अधिकारों का वास्तविक लाभ तभी मिल सकता है जब महिलाएं स्वयं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों।

समाज का भी यह दायित्व है कि वह महिलाओं को सम्मान और समान अवसर प्रदान करे। जब बेटियों को शिक्षा, सुरक्षा और समान अधिकार मिलेंगे तभी समाज का वास्तविक विकास संभव होगा।

इस प्रकार, बेटी और महिलाओं के कानूनी अधिकार केवल कानून की किताबों तक सीमित नहीं रहने चाहिए बल्कि उन्हें समाज में पूर्ण रूप से लागू किया जाना चाहिए ताकि हर महिला सुरक्षित, सम्मानित और आत्मनिर्भर जीवन जी सके।

आज के समय में बेटियां किसी भी दृष्टि से बेटों से कम नहीं हैं। कानून ने भी इस बात को स्वीकार करते हुए उन्हें संपत्ति में समान अधिकार प्रदान किया है। Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 और न्यायालयों के निर्णयों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बेटियों का अधिकार जन्मसिद्ध और पूर्ण है।

इसलिए आवश्यक है कि समाज में जागरूकता बढ़ाई जाए और बेटियों को उनके अधिकार दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट का सख्त फैसला : अब आसानी से नहीं मिलेगा स्थगन, जारी हुए नए नियम

नई दिल्ली। Supreme Court of India ने मामलों में बार-बार स्थगन लेने की प्रवृत्ति पर लगाम लगाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जारी सर्कुलर के अनुसार अब केवल विशेष परिस्थितियों में ही मामलों की सुनवाई टाली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक, अब स्थगन के लिए आवेदन एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड या स्वयं पक्षकार द्वारा ही किया जा सकेगा। आवेदन करने वाले को पहले ही दूसरी पक्ष को इसकी जानकारी देना अनिवार्य होगा और सेवा का प्रमाण पिछली कार्य दिवस सुबह 11 बजे से पहले जमा करना होगा। वहीं, दूसरी पक्ष को दोपहर 12 बजे तक आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार दिया गया है।

नए नियमों में स्पष्ट किया गया है कि स्थगन केवल असाधारण परिस्थितियों—जैसे पारिवारिक शोक, गंभीर बीमारी या अन्य ठोस कारण—में ही दिया जाएगा। साथ ही, आवेदन में स्थगन का स्पष्ट

कारण और पहले लिए गए स्थगनों की संख्या बताना जरूरी होगा। सर्कुलर के अनुसार, नए मामलों में स्थगन का अनुरोध केवल एक बार ही स्वीकार किया जाएगा, जबकि लगातार दो बार स्थगन की अनुमति नहीं होगी, जब तक मामला कोर्ट में सूचीबद्ध न हो। इसके अलावा, नियमित मामलों में स्थगन के लिए कोई पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी स्थगन आवेदन निर्धारित प्रारूप में ईमेल के जरिए ही भेजे जाएंगे। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इन नए नियमों से मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी और अनावश्यक देरी पर रोक लगेगी।

अब आसानी से नहीं मिल सकेगी बार-बार तारीख— अब



अदालतों में बार-बार तारीख लेने की आदत पर सख्त लगाम लगने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टालने के नियमों को कड़ा करते हुए साफ कर दिया है कि अब तारीख पे तारीख का दौर लगभग खत्म होगा और सिर्फ बेहद जरूरी हालात में ही सुनवाई टाली जाएगी।

कोर्ट की ओर से 18 मार्च को जारी सर्कुलर में कहा गया है कि पहले के 29 नवंबर 2025 और 2 दिसंबर 2025 वाले निर्देशों की जगह अब नया नियम लागू होगा।

इसके तहत अलग-अलग तरह के मामलों के लिए अलग नियम तय किए गए हैं।

एडजर्नमेंट मांगने वाले को बतानी होगी ठोस वजह— इतना ही नहीं, दूसरी पार्टी को भी इस पर आपत्ति जताने का मौका मिलेगा। वह दोपहर 12 बजे तक ईमेल के जरिए अपनी आपत्ति दर्ज करा सकती है, जिसे कोर्ट के सामने रखा जाएगा। कोर्ट ने यह भी अनिवार्य कर दिया है कि एडजर्नमेंट मांगने वाले को ठोस वजह बतानी होगी और यह भी बताना होगा कि पहले कितनी बार तारीख ली जा चुकी है। बिना वजह के अब सुनवाई टालना संभव नहीं होगा।

कब मिल सकेगी अगली तारीख?— सर्कुलर के मुताबिक, सिर्फ असाधारण परिस्थितियों में ही तारीख

मिलेगी। जैसे परिवार में किसी की मौत, गंभीर बीमारी या कोई और ठोस और वास्तविक कारण, जिसे कोर्ट संतोषजनक माने। इसके अलावा बार-बार तारीख लेने पर भी रोक लगा दी गई है। फ्रेश मामलों में एडजर्नमेंट की अर्जी सिर्फ एक बार ही दी जा सकेगी। साथ ही, लगातार दो बार सुनवाई टालने की अनुमति नहीं होगी। चाहे मांग किसी भी पक्ष ने की हो। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि एडजर्नमेंट की अर्जी तय फॉर्मेट में ही देनी होगी और इसे तय ईमेल आईडी पर भेजना होगा। कुल मिलाकर, सुप्रीम कोर्ट का यह कदम न्याय प्रक्रिया को तेज करने की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है, जिससे लंबित मामलों के बोझ को कम करने में मदद मिल सकती है।

महिला कांग्रेस ने भोपाल के हॉस्टलों में दिए इंडक्शन चूल्हे

राजिग इन्दौर

रिपोर्टर

भोपाल में गैस सिलिंडर की कमी को लेकर सियासत तेज हो गई है। महिला कांग्रेस ने गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं को इंडक्शन चूल्हे बांटकर विरोध जताया और सरकार पर गैस संकट को लेकर लापरवाही का आरोप लगाया। छात्राओं ने बताया कि एलपीजी की कमी से भोजन व्यवस्था प्रभावित हुई है।



बनाना भी संभव नहीं रह गया था। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रीना बोरासी के नेतृत्व में टीम हॉस्टल पहुंची। यहां उन्होंने खुद इंडक्शन पर चाय बनाकर उसका इस्तेमाल दिखाया और इसे राहत का छोटा लेकिन जरूरी कदम बताया।

सरकार पर सीधा हमला

रीना बोरासी ने आरोप लगाया कि सरकार गैस उपलब्ध होने के दावे कर रही है, लेकिन हकीकत में लोग अब भी लाइन में खड़े हैं। उन्होंने कहा कि गैस की कमी का सबसे ज्यादा असर उन छात्राओं पर पड़ रहा है, जो परिवार से दूर रहकर पढ़ाई कर रही हैं।

और हॉस्टलों तक पहुंचेगा अभियान

महिला कांग्रेस ने साफ किया है कि यह

अभियान यहीं नहीं रुकेगा। आने वाले दिनों में शहर के अन्य हॉस्टलों में भी जाकर छात्राओं को इंडक्शन दिए जाएंगे और उनकी समस्याएं सुनी जाएंगी। महिला कांग्रेस अध्यक्ष रीना बोरासी ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण गैस सिलिंडर के दाम आम जनता की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। विशेष रूप से छात्रावासों में रहने वाली छात्राओं और कामकाजी महिलाओं के लिए रसोई का खर्च संभालना बेहद कठिन हो गया है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष रीना बोरासी ने आगे कहा कि हमेशा महिलाओं के हितों के लिए संघर्ष करती रही हैं और यह पहल उसी कड़ी का हिस्सा है। इंडक्शन चूल्हों का वितरण एक संदेश है कि जब सरकार राहत देने में असफल होती है, तब कांग्रेस आगे आकर जनता के साथ खड़ा होती है।

अप्रैल के दूसरे हफ्ते में आएंगे 10वीं 12वीं के रिजल्ट

एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के परिणाम अप्रैल के दूसरे सप्ताह में आने की संभावना है। लगभग 16 लाख छात्रों ने परीक्षा दी है और 20 हजार शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन कार्य तेजी से चल रहा है। वहीं कक्षा 5वीं और 8वीं के परिणाम इसी सप्ताह घोषित होने की संभावना है, जिनका मूल्यांकन पूरा हो चुका है। माध्यमिक शिक्षा मंडल (मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल) की कक्षा 10वीं और 12वीं के वार्षिक परीक्षा परिणाम अप्रैल के दूसरे सप्ताह में घोषित किए जाने की संभावना है। स्कूल शिक्षा विभाग ने मूल्यांकन कार्य को समय पर पूरा करने के लिए सभी केंद्रों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। वहीं कक्षा 5वीं और 8वीं के परिणाम इसी सप्ताह घोषित होने की प्रबल संभावना है। दोनों कक्षाओं की परीक्षाओं में करीब 16 लाख विद्यार्थियों ने भाग लिया है। उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य में लगभग 20 हजार शिक्षक लगाए गए हैं और प्रक्रिया तेजी से अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है। विभाग का लक्ष्य है कि परिणाम समय पर जारी कर छात्रों को आगे की पढ़ाई और करियर प्लानिंग के लिए पर्याप्त समय मिल सके। अधिकारियों के अनुसार मूल्यांकन केंद्रों पर कार्य को तेज किया गया है। अंतिम चरण में पहुंचते ही रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, ताकि निर्धारित समय सीमा में परिणाम घोषित किए जा सकें। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जो छात्र केवल दो विषयों में अनुत्तीर्ण होंगे, उन्हें जून में पुनः परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। इससे छात्रों का पूरा वर्ष खराब होने से बचाया जा सकेगा। कक्षा 5वीं और 8वीं के परिणाम इसी सप्ताह घोषित होने की प्रबल संभावना है। इन परीक्षाओं का आयोजन राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश द्वारा किया गया था। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरा हो चुका है। 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं फरवरी 2026 में आयोजित हुई थीं। रिजल्ट की अंतिम तारीख की घोषणा जल्द ही आधिकारिक पोर्टल पर की जाएगी।

कलेक्टर से मिलने के लिए पूरे दिन बैठी रही जिला पंचायत अध्यक्ष

राजिग इन्दौर

रिपोर्टर



मीशा सिंह ने जिला पंचायत अध्यक्ष लालबाई चंद्रवंशी से पूरे दिन इंतजार कराया पर मुलाकात नहीं की। जब कलेक्टर अपने कार्यालय से निकल रही थीं तब जिला पंचायत अध्यक्ष सामने खड़ी थीं,

लेकिन कलेक्टर उनसे मिले बिना ही निकल गए। इसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष कलेक्टर कार्यालय में ही धरने पर बैठ गईं। मध्य प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष को राज्य मंत्री के समक्ष माना गया है। जनप्रतिनिधियों से समन्वय नहीं होने के चलते ही सीधी कलेक्टर को मुख्यमंत्री ने हटाया था। आक्रोश को देखते हुए लगता है कि अगला नंबर रतलाम जिले का हो सकता है। कलेक्टर मिशा सिंह ने लोकल मीडिया को बताया कि सोमवार को समय-सीमा में होने वाले कार्य की समीक्षा बैठक सहित अन्य कई बैठक लगातार चलीं, जिसके चलते व्यस्तता अधिक थी।

इस सप्ताह आपके सितारे

25 मार्च 2026 से 31 मार्च 2026

किसी के यहां होंगे शुभ कार्य तो किसी के कारोबार में होगी वृद्धि

मेष - इस सप्ताह भूमि अथवा वाहन संबंधी कोई कार्य होगा। स्वयं का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

किसी व्यक्ति का विपरीत व्यवहार पीड़ित कर सकता है। संतान से भी कुछ कष्ट संभव है। जीवनसाथी का स्वास्थ्य एवं सहयोग अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में धनात्मकता रहेगी।

वृषभ - कारोबार की दृष्टि से यह सप्ताह शुभ है। आवक अच्छी होगी। व्यय भी अधिक होंगे। स्वयं के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाहन सुख उतम है। कोई यात्रा संभव है। घर में किसी शुभ कार्य होने की रूपरेखा बनेगी। जीवनसाथी के व्यवहार से संतोष रहेगा।

मिथुन - इस सप्ताह प्रेम संबंधों की प्रति सावधान रहें। जीवनसाथी से कष्ट संभव है। कारोबार ठीक ठीक रहेगा। आवक मध्यम, व्यय अधिक। संतान पक्ष ठीक रहेगा। इस सप्ताह बेवजह के विवादों से बचें। पिता को आधिक कष्ट हो सकता है। रुका हुआ कुछ पैसा मिलेगा।

कर्क - इस सप्ताह किसी से बेवजह का विवाद हो सकता है। सावधान रहें। कारोबार अच्छा चलेगा। मान सम्मान में वृद्धि संभव है। किसी कार्य के होने से संतोष मिलेगा। जीवनसाथी का स्वास्थ्य एवं व्यवहार अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध सुधरेंगे। वाहन में टूट फूट संभव है।

सिंह - इस सप्ताह मानसिक तनाव कम होंगे। बहुप्रतीक्षित कोई कार्य होगा। मित्र सहयोग करेंगे। जीवनसाथी का स्वास्थ्य नरम-गरम रहेगा। प्रेम संबंध ठीक ठीक रहेंगे। वाहन में टूट-फूट संभव है। संतान पक्ष कुछ पीड़ित करेगी। विद्यार्थीगण परेशान रहेंगे। मान सम्मान में वृद्धि होगी।

कन्या - शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से सप्ताह ठीक नहीं। कारोबार में विघ्न आएंगे। संतान पक्ष ठीक रहेगा। जीवनसाथी का सहयोग और व्यवहार आपको मानसिक सुकून देने वाला होगा। शत्रु सिर उठा सकते हैं। लाभ सीमित होंगे।

कुंभ - इस सप्ताह संतान संबंधी कोई कार्य होगा। व्यय अधिक होगा। कारोबार की दृष्टि से सप्ताह श्रेष्ठ है। मित्रों का सहयोग अच्छा मिलेगा। शत्रु परास्त होंगे। भूमि संबंधी कोई कार्य होगा। वाहन सुख उतम। स्वास्थ्य की दृष्टि से धनात्मकता रहेगी।

मीन - इस सप्ताह किसी कार्य की कोई योजना फनूिभूत होती दिखाई देगी। प्रेम संबंध खूब फले-फूलेंगे। संतान पक्ष अल्प कष्ट देगा। दूरस्थ यात्रा के प्रबल योग बन रहे हैं। व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से धनात्मकता रहेगी। बेवजह के विवादों को टालें। आवक अच्छी होगी किंतु व्यय अधिक होंगे।

तुला - शारीरिक स्वास्थ्य इस सप्ताह अच्छा रहेगा। संतान पक्ष पीड़ित करेगा। जीवनसाथी का स्वास्थ्य और व्यवहार ठीक-ठीक रहेगा। प्रेम संबंधों में सावधानी रखें। शत्रु परास्त होंगे। मित्र सहयोग करेंगे। किसी शुभ कार्य होने की संभावना है। किसी से बेवजह विवाद न करें। भूमि, वाहन से कष्ट।

वृश्चिक - इस सप्ताह मानसिक परेशानी ज्यादा रहेगी। किसी का विपरीत व्यवहार कष्ट देगा। जीवनसाथी का स्वास्थ्य और सहयोग अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध फले फूलेंगे। संतान पीड़ित करेगी। लाभ में कमी आएगी। कारोबार मध्यम रहेगा। वाहन सावधानी से चलावें। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

धनु - इस सप्ताह प्रेम संबंधों के प्रति बहुत अधिक सावधान रहें। अवस्था कोई परेशानी हो सकती है। माता का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं रहेगा। वाहन से कष्ट होगा। विवादों से बचें। कारोबार अच्छा रहेगा। शत्रु दबेंगे। स्वयं का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। व्यय अधिक होंगे।

मकर - किसी व्यक्ति के धनात्मक व्यवहार से आपको खुशी मिलेगी घर में अमूमन शांति एवं प्रसन्नता रहेगी। कारोबार अच्छा चलेगा। आवक भी अच्छी होगी किंतु बेवजह कुछ नुकसान संभव है। वाहन सुख श्रेष्ठ है। संतान पक्ष से कुछ कष्ट संभव है। विवादों से बचें।

कुंभ - इस सप्ताह संतान संबंधी कोई कार्य होगा। व्यय अधिक होगा। कारोबार की दृष्टि से सप्ताह श्रेष्ठ है। मित्रों का सहयोग अच्छा मिलेगा। शत्रु परास्त होंगे। भूमि संबंधी कोई कार्य होगा। वाहन सुख उतम। स्वास्थ्य की दृष्टि से धनात्मकता रहेगी।

मीन - इस सप्ताह किसी कार्य की कोई योजना फनूिभूत होती दिखाई देगी। प्रेम संबंध खूब फले-फूलेंगे। संतान पक्ष अल्प कष्ट देगा। दूरस्थ यात्रा के प्रबल योग बन रहे हैं। व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से धनात्मकता रहेगी। बेवजह के विवादों को टालें। आवक अच्छी होगी किंतु व्यय अधिक होंगे।



श्रीमान उमेश पांडे
ज्योतिष एवं वास्तुविद
महात्मा गांधी मार्ग, मल्हारगंज, इंदौर (म.प्र.)
मो. 8602912030

इस सप्ताह की गृह स्थितियां

- सूर्य - मीन ■ चंद्र - कुंभ से वृषभ ■ मंगल - कुंभ ■ बुध - कुंभ वक्री
- गुरु - मिथुन ■ शुक - मीन में ■ शनि - मीन ■ राहु - कुंभ
- केतु - सिंह

1 अप्रैल से महंगी हो जाएगी बिजली

प्रदेश में 1 अप्रैल से बिजली महंगी हो सकती है। दरअसल, बिजली कंपनियों ने 10 प्रतिशत टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। ऐसे में महीने में औसत 300 रुपए तक बिजली बिल बढ़ सकता है।

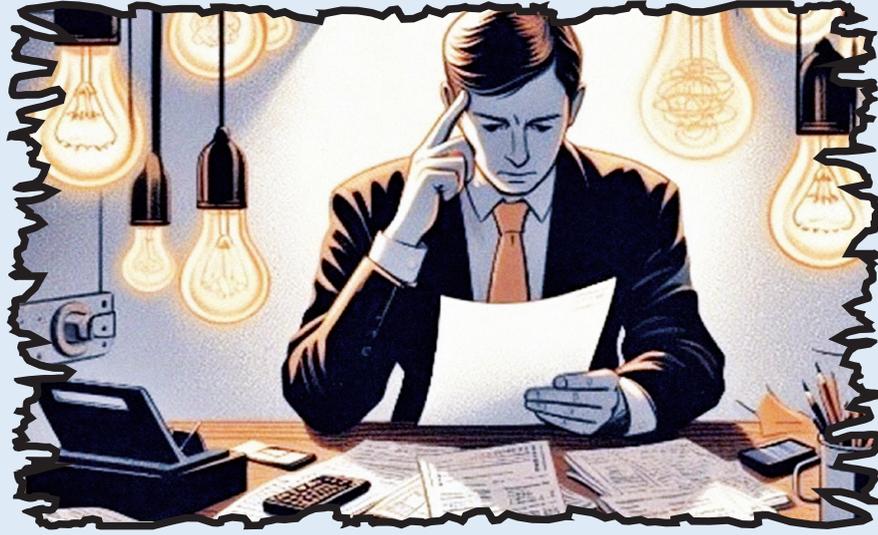
राजिग इन्दौर ■ रिपोर्टर

नए वित्तीय वर्ष में बिजली उपभोक्ताओं को झटका लगने वाला है। प्रदेश में 01 अप्रैल 2026 से बिजली महंगी हो सकती है। दरअसल, बिजली कंपनियों ने 10 प्रतिशत टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव के मुताबिक, महीने में औसत 300 रुपए तक बिजली बिल में बढ़ोतरी हो सकती है। एमपी में बिजली महंगी हो सकती है। बिजली वितरण कंपनियों ने राज्य विद्युत नियामक आयोग को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्ताव भेजा है, जिसमें बिजली की दरों में 10.19 फीसद बढ़ोतरी की बात कही गई है। ये प्रस्ताव अगर मंजूर हुआ तो औसत महीने में 300 रुपए तक बिजली बिल में बढ़ोतरी हो सकती है। प्रपोजल के मंजूर होने पर नई दरें 01 अप्रैल 2026 से लागू की जाएंगी। बिजली की दरें बढ़ने से घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगेगा।

6000 करोड़ का घाटा

बिजली वितरण कंपनियों ने 2026-27 के लिए 6,000 करोड़ रुपये से अधिक के अनुमानित राजस्व घाटे का हवाला दिया है। उन्होंने इस बोझ को उपभोक्ताओं पर डालने की मांग की है।

यदि यह प्रस्ताव मंजूर हुआ, तो एक करोड़ से



अधिक घरेलू उपभोक्ताओं पर सालाना 3600 रुपए से अधिक का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जिससे मासिक बिल में लगभग 300 रुपए की वृद्धि होगी। कंपनियां बढ़ते घाटे, परिचालन खर्चों में वृद्धि और अन्य वित्तीय चुनौतियों को दरें बढ़ाने का मुख्य कारण बता रही हैं।

कोयले पर जीएसटी हटाने का भी प्रभाव नहीं- बिजली दर बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं, जो बिजली कंपनियों और सरकार की मंशा पर संदेह पैदा कर रहे हैं। पिछले

साल केंद्र सरकार ने बिजली बनाने में मुख्य इस्तेमाल होने वाले कोयले पर लगने वाला 400 रुपए प्रति टन का जीएसटी सेस (कंपेंसेशन सेस) पूरी तरह हटा दिया था। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे बिजली बनाने की लागत में प्रति यूनिट 17 से 18 पैसे की कमी आनी चाहिए थी। लेकिन कंपनियां उपभोक्ताओं को यह फायदा देने की बजाय 10.19 प्रतिशत की बढ़ोतरी मांग रही हैं, जिससे लगता है कि बचत का फायदा उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच रहा।

50 यूनिट तक
मौजूदा दर - 4.45 रुपए प्रति यूनिट
प्रस्तावित दर - 4.78 रुपए प्रति यूनिट
51 से 150 यूनिट तक
मौजूदा दर - 5.41 रुपए प्रति यूनिट
प्रस्तावित दर - 5.82 रुपए प्रति यूनिट
151 से 300 यूनिट
मौजूदा दर - 6.79 रुपए प्रति यूनिट
प्रस्तावित दर - 7.3 रुपए प्रति यूनिट
300 यूनिट से ऊपर
मौजूदा दर - 8.98 रुपए प्रति यूनिट
प्रस्तावित दर - 7.3 रुपए प्रति यूनिट

प्रस्ताव में 151 से 300 यूनिट वाले स्लैब को समाप्त कर उसे 300 यूनिट से ऊपर वाले स्लैब में विलय करने की भी बात कही गई है। इससे 151-300 यूनिट वाले उपभोक्ताओं के लिए दरें बढ़ जाएंगी। बिजली कंपनियों ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि उन्हें लगातार बढ़ा घाटा हो रहा है। परिचालन खर्च बढ़ गए हैं और अन्य वित्तीय चुनौतियां भी हैं। इस बार पावर मैनेजमेंट कंपनी ने कुल 6,044 करोड़ रुपए के घाटे को भरने के लिए ये मांग की है।

बंगाल में बीजेपी का फुल एक्शन प्लान, पीएम मोदी की 14 रैलियां तय

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। सत्तारूढ़ सरकार को चुनौती देने के लिए बीजेपी ने इस बार व्यापक प्रचार अभियान की तैयारी की है।

पार्टी के शीर्ष नेताओं का राज्य में दौरा शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने पश्चिम बंगाल में 14 रैलियां और रोडशो करेंगे। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने इन कार्यक्रमों की पुष्टि की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी चुनाव प्रचार में सक्रिय रहेंगे। उनके कम से कम 8 रैलियों और रोडशो का कार्यक्रम तय किया गया है। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन राज्य में सात सभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के छह कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं।

योगी आदित्यनाथ और मिथुन चक्रवर्ती भी करेंगे प्रचार

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पश्चिम बंगाल में जनसभाएं और रोडशो करेंगे। उनके लगभग 8 कार्यक्रम तय किए गए हैं। अभिनेता से नेता बने मिथुन चक्रवर्ती भी चुनाव प्रचार में सक्रिय रहेंगे और करीब 10 सभाओं में हिस्सा लेंगे।

दो चरणों में होगा मतदान

राज्य में विधानसभा चुनाव दो चरणों में आयोजित किए जाएंगे। पहले चरण में 23 अप्रैल को 152 सीटों पर मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण में 29 अप्रैल को 142 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मतगणना 4 मई को होगी, जिसके बाद नई सरकार का गठन तय होगा। बीजेपी ने 111 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इसमें संदेशखिल आंदोलन से जुड़ी रेखा पात्रा और पूर्व केंद्रीय मंत्री निशीथ अधिकारी को शामिल किया गया है। अन्य प्रमुख उम्मीदवारों में अर्जुन सिंह, तपस राय और रूपा गांगुली शामिल हैं। रूपा गांगुली सोनारपुर दक्षिण सीट से चुनाव लड़ेंगी। अधिवक्ता प्रियंका तिब्रेवाल को एंटांली सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। उन्होंने पहले भी चुनावी मुकाबले में हिस्सा लिया था। राज्य में कई सीटों पर हाई प्रोफाइल मुकाबले देखने को मिल सकते हैं, जिससे चुनावी मुकाबला और रोचक होने की संभावना है।

आश्रम में छापे जा रहे थे नकली नोट चीन से मंगवाया कागज और चैट जीपीटी की मदद से छापे नोट

अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने नकली नोटों के एक बड़े नकली नोटों के रैकेट का मंडाफोड़ किया है। इसमें नेटवर्क के अन्य सभी कनेक्शन, वित्तीय लेनदेन और अंतरराज्यीय-अंतरराष्ट्रीय संबंधों की जांच जारी है।

क्राइम ब्रांच ने नकली नोटों के एक बड़े रैकेट का मंडाफोड़ किया है और 2.38 करोड़ रुपये के जाली नोट बरामद किए। क्राइम ब्रांच ने इस मामले में एक महिला समेत सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों ने बताया है कि ये आरोपी ChatGPT AI और चीन से मंगाए गए सिक्वोरिटी थ्रेड पेपर का इस्तेमाल कर रहे थे और इसके जरिए 500 रुपये के हाई क्वालिटी फर्जी नोट छाप रहे थे।

फर्जी करेंसी के मामले में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। क्राइम ब्रांच के डीसीपी अजीत राजयान ने बताया कि 18 मार्च को अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को एक सूचना मिली। मामले की जांच के बाद अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने छानबीन की। जांच में पता चला कि सात लोग हाई क्वालिटी वाले नकली भारतीय नोटों की तस्करी कर रहे थे। डीसीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया खुलासा



डीसीपी ने बताया कि पूछताछ में पता चला कि इन व्यक्तियों ने चीन से उच्च गुणवत्ता वाले कागज और अन्य सामग्री आयात करने के लिए इन नकली नोटों का इस्तेमाल किया था। इस उच्च गुणवत्ता वाले कागज और सामग्री में पहले से ही कुछ सुरक्षा विशेषताएं मौजूद थीं। बाद में पता चला कि आरोपियों ने उच्चतम प्रिंटिंग गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अपने औद्योगिक-ग्रेड प्रिंटर को कॉन्फिगर करने के लिए चैटजीपीटी और अन्य एआई टूल का इस्तेमाल किया था।

मशीनें भी बरामद

क्राइम ब्रांच के मुताबिक, इन सातों आरोपियों से पूछताछ जारी है और पुलिस रिमांड मांगेगी। गिरफ्तार आरोपियों में मुकेश थुम्मर की अहम भूमिका है। प्रारंभिक जांच से पता

चलता है कि वे गुजरात में ही सक्रिय थे। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने आरोपियों से रंगे हाथों 2.1 करोड़ रुपये से अधिक के नोट जब्त किए।

अधिकारियों के मुताबिक, आगे की पूछताछ के बाद अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने सूरत पुलिस की मदद से सूरत में तलाशी अभियान चलाया और 28 लाख रुपये के साथ-साथ प्रिंटिंग सामग्री और प्रिंटिंग मशीनें भी बरामद की।

कार्रवाई को लेकर एजेंसी का कहना है कि देश की वित्तीय प्रणाली को बड़ा खतरा टल गया है, क्योंकि उच्च गुणवत्ता की नकली करेंसी का प्रसार आर्थिक स्थिरता और लोगों के भरोसे को प्रभावित कर सकता है। यह कार्रवाई एक बड़े सप्लाई नेटवर्क को खत्म करने में भी अहम रही।

हर 46 दिन में एक अफसर पर कार्रवाई

सवा दो साल में 18 आईएएस- आईपीएस पर विवक एक्शन

सीएम मोहन ने प्रशासनिक लापरवाही के मामले में फिर लिया सख्त फैसला

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक बार फिर सख्त प्रशासनिक संदेश देते हुए गुना के एसपी अंकित सोनी और सीधी के कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी को लापरवाही के मामले में हटाया है। यह कार्रवाई साफ संकेत है कि गंभीर चूक पर सरकार किसी भी स्तर पर ढील देने के मूड में नहीं है। करीब सवा दो साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री ने हर 46 दिन के अंतराल में औसतन एक अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की गई।

राजिग इन्दौर

रिपोर्टर

दरअसल, 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से ही डॉ. यादव ने अपनी कार्यशैली में सख्ती का रुख अपनाया है। करीब सवा दो साल के कार्यकाल में उन्होंने अब तक कलेक्टर रहे 10 आईएएस व 8 एसपी व अन्य सीनियर आईपीएस अफसरों को कार्रवाई का सामना करना पड़ा है।

अब तक कम से कम 9 ऐसे बड़े मामले सामने आए हैं, जिनमें सीधे तौर पर कलेक्टर और एसपी स्तर के अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा वरिष्ठ आईपीएस और राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों पर भी सख्त कदम उठाए गए हैं।

रिश्व कांड में एसपी, दफतर में नहीं बैठने पर सीधी कलेक्टर पर कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने गुना एसपी अंकित सोनी को 22 मार्च को उनके जिले में गुजरात के व्यापारी से एक करोड़ रुपए जब्त करने के बाद पुलिस द्वारा बीस लाख रुपए लेकर छोड़ देने और कोई कार्यवाही नहीं करने पर हटा दिया है। यहां थाना प्रभारी समेत चार पुलिसकर्मी सस्पेंड भी हुए हैं।

इसी तरह सीधी जिले के कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी को भी शिकायतों पर हटाया गया है। दावा किया जा रहा है कि सोमवंशी कलेक्टर दफतर में नाम मात्र बैठते थे। वे अकसर शाम को कुछ देर के लिए ही दफतर आते थे। इससे लोगों और जनप्रतिनिधियों में नाराजगी थी। यह भी सूचना है कि सीधी सांसद के एक प्रोजेक्ट पर फायर एनओसी रोक रखी थी।

आनंदपुर साहिब ट्रस्ट रिश्वतकांड : अशोकनगर कलेक्टर को हटाया

अशोकनगर में आनंदपुर साहिब ट्रस्ट के खिलाफ कार्यवाही में रिश्वत के आरोप के चलते 24 जनवरी को अशोकनगर कलेक्टर रहे आदित्य सिंह को हटा दिया था। हालांकि बाद में ट्रस्ट की ओर से कलेक्टर के खिलाफ किसी तरह की शिकायत नहीं किए जाने की बात मीडिया से कही गई थी।

सिंह की जगह कर्मचारी चयन मंडल में पदस्थ साकेत मालवीय को अशोकनगर कलेक्टर की कमान सौंपी गई है। आदित्य सिंह ने चुनाव आयोग की एसआईआर की कार्यवाही में प्रदेश में सबसे अच्छा काम किया था।



दूषित पानी से मौतें : इंदौर निगमायुक्त, अपर आयुक्त पर कार्रवाई

इंदौर के भागीरथपुरा में सीवर युक्त पानी की सप्लाई के बाद हुई 23 मौतों के बाद 2 जनवरी को नगर निगम आयुक्त दिलीप यादव को हटा दिया गया। उन्हें पहले ग्रामीण विकास विभाग में उप सचिव फिर पर्यटन निगम में नियुक्ति दी गई। इसी दिन नगर निगम के अपर आयुक्त रोहित सिंसोनिया को हटाकर मंत्रालय में उपसचिव पदस्थ किया गया।

अगले दिन 3 जनवरी को मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के एमडी क्षितिज सिंघल को निगमायुक्त और आकाश सिंह, प्रखर सिंह और आशीष पाठक को अपर आयुक्त बनाकर भेजा।

मऊगंज गड़रा हत्याकांड कलेक्टर-एसपी को हटाया

15 मार्च 2025 को मऊगंज के गड़रा गांव में विवाद में पुलिसकर्मी की हत्या और तनाव के बाद 18 मार्च को कलेक्टर और एसपी को बदला।

कलेक्टर अजय श्रीवास्तव को हटाकर उप सचिव लोक परिसंपत्ति प्रबंधन और खेल एवं युवा कल्याण विभाग में पदस्थ किया गया और उनकी जगह 2015 बैच के आईएएस संजय कुमार जैन को कलेक्टर बनाया गया। एसपी रसना ठाकुर को हटाकर एआईजी पीएचक्यू भोपाल भेजा गया था। रसना की जगह दिलीप कुमार सोनी को एसपी बनाया।

गड़रा गांव में आदिवासी परिवार द्वारा बंधक बनाए गए युवक सनी द्विवेदी की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी जिसे बचाने गई पुलिस टीम पर हुए हमले में एएसआई रामगोविंद गौतम की

मौत हुई थी तथा तहसीलदार सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे।

सागर में दीवार गिरी : कलेक्टर-एसपी, एसडीएम पर कार्रवाई

सागर जिले के शाहपुर में मकान की दीवार गिरने से 9 बच्चों की मौत हो गई। सरकार ने 4 अगस्त 2024 को कलेक्टर दीपक आर्य, एसपी अभिषेक तिवारी और एसडीएम संदीप सिंह को हटा दिया। आर्य को पहले मंत्रालय पदस्थ किया, सात दिन बाद एमपी ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण का सीईओ बना दिया था।

दूसरी ओर एसपी अभिषेक तिवारी को हटाने के बाद यह बात सामने आई थी कि वे घटना से 15 दिन पहले से विदेश में थे। वे 5 महीने पहले से तबादला चाह रहे थे। केंद्र में प्रतिनियुक्ति का आदेश जारी होने के बावजूद सरकार उन्हें रिलीव नहीं कर रही थी। हालांकि छुट्टी से लौटने के बाद रिलीव कर दिया गया।

झाड़वर की औकात पर हटाया था

शाजापुर कलेक्टर किशोर कान्याल को

देश भर में ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल के बीच 2 जनवरी 2024 को शाजापुर कलेक्टर और ड्राइवर्स की बैठक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसमें कलेक्टर मीटिंग के दौरान एक ड्राइवर से औकात पूछते नजर आ रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद में कलेक्टर ने अफसोस प्रकट किया।

हालांकि सरकार ने 3 जनवरी को उन्हें हटाकर मंत्रालय में उप सचिव पदस्थ किया कर दिया। 25 दिन बाद 28 जनवरी को उन्हें वन विभाग में उप सचिव बनाकर भेजा।

हरदा में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद पहले एसपी फिर कलेक्टर को हटाया

हरदा में 7 फरवरी 2024 को पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत और 75 से अधिक घायल होने पर पहले एसपी संजीव कुमार कंचन और फिर कलेक्टर ऋषि गर्ग को हटा दिया था। कारखाना निरीक्षक एवं सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा नवीन कुमार बरवा को निलंबित किया गया था। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सिवनी कलेक्टर क्षितिज सिंघल और एसपी राकेश कुमार सिंह को 23 जून को हटा दिया था। सिंघल को मध्या क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का प्रबंध संचालक बनाया गया था। वहीं शेवा नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन को सिवनी कलेक्टर बनाकर भेजा था। संस्कृति फिलहाल भोपाल नगर निगम की आयुक्त हैं। इसी तरह एसपी राकेश कुमार सिंह को हटा कर पुलिस मुख्यालय में सहायक पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया। वे फिलहाल छिंदवाड़ा एसपी हैं। उस समय इंदौर देहात के पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मेहता को सिवनी का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया था।

गुना में बस में आग लगी कलेक्टर, एसपी और परिवहन आयुक्त को हटाया

डॉ. मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के 15 दिन के भीतर 27 दिसम्बर 2023 को गुना जिले में बस में आग लगने से 13 लोगों की मौत हो गई थी। सीएम ने 28 दिसम्बर को गुना कलेक्टर तरुण राठी और एसपी विजय कुमार खत्री के साथ ही परिवहन आयुक्त संजय कुमार झा को हटा दिया था।

इसके साथ ही आरटीओ रवि बरेलिया और गुना के चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर बीडी कतरोलिया को सस्पेंड कर दिया गया था। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव सुखवीर सिंह से परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव का अतिरिक्त प्रभार वापस ले लिया गया। परिवहन विभाग में पदस्थ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अरुण कुमार सिंह की सेवाएं भी सामान्य प्रशासन विभाग में वापस की गईं।

कलेक्टर राठी को एक माह तक नई जिम्मेदारी के लिए इंतजार करना पड़ा था। उन्हें 28 जनवरी को जारी आदेश में वाल्मी (वाटर एंड लैण्ड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट) के संचालक की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

सीएसपी के पति की शिकायत पर कटनी एसपी अभिजीत रंजन को हटाया

कटनी जिले के एसपी अभिजीत रंजन जिले में पदस्थ सीएसपी को लेकर विवादों में रहे थे। सीएसपी के तहसीलदार पति और उनके परिजनों ने इसकी शिकायत सीएम, डीजीपी समेत अन्य सभी अधिकारियों को की थी। जब लंबे समय तक विवाद चला तो जून 2025 में कटनी एसपी रंजन को पुलिस मुख्यालय अटैच किया गया।